विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। –रस्किन

संसद का विशेष सत्र- बूझो तो जानें

संसद का विशेष सत्र जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर, 2023 तक होगा, सबके लिए एक पहेली की तरह सिद्ध हो रहा है । जनता को तो छोड़िए, मीडिया तक को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस विशेष संसद सत्र को क्यों बुलाया गया है और इसमें किन विषयों पर चर्चा होनी है? राजनीतिक दल एवं अन्य राजनीतिक पंडिते भी अपनी-अपनी दृष्टि से केवल अनुमान ही लगा रहे हैं। सरकार सामान्यता स्वयं ही स्पष्ट कर देती है कि विशेष सत्र का उद्देश्य क्या है ? ऐसा इस बार कुछ नहीं किया गया है, इसीलिए अफवाहों का बाजार गर्म है। इस लेख में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस विशेष सत्र का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार के विषय इसमें लिए जा सकते हैं?

यह मान कर चलना गलत नहीं होगा कि यह विशेष सत्र आगामी कुछ माह में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव एवं मई, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही बुलाया गया है। अत: यह तो स्वाभाविक है कि इस सत्र का प्रमुख उद्देश्य भाजपा द्वारा चुनाव में सफलता को सुनिश्चित किया जाना होगा। ऐसा अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि गत कुछ दिनों में जब से विपक्षी दलों ने एक जुट होकर 'इंडिया'(INDIA) के नाम से गठबंधन बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए में कुछ घबराहट सी दिखाई देती है। भाजपा जितनी निश्चिंत पहले थी उतनी वर्तमान में दिखाई नहीं देती । इसलिए स्वाभाविक है कि वह मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए संसद का विशेष सत्र ही क्यों न बुलाया जाए।

पहला अनुमान तो यही है कि संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन करके देश का नाम केवल 'भारत' ही रख दिया जाए । वर्तमान में हिंदी में भारत एवं अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और इसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद एक में है। विश्व भर में भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। जब से विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया (Indian National Developmental Inclusive Alliance) रखा है, तब से भाजपा एवं प्रधानमंत्री मोदी इस इंडिया नाम का ही मज़ाक बनाने में लगे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि देश के नाम से भी इंडिया हटाने का प्रयास जारी है। संवैधान विशेषज्ञों का मानना है कि नाम परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। न केवल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 'भारत' नाम करने पर पता नहीं किन-किन स्थानों पर परिवर्तन करना होगा? अब सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ भारत कहलाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम में से भी इंडियन शब्द को हटाना होगा। इंडियन आर्मी को भी क्या अंग्रेजी में भारतीय आर्मी ही कहा जाएगा। इसके बदलाव की प्रक्रिया में कितना धन और श्रम लगेगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जब सड़कों, शहरों और योजनाओं का नाम बदलने से काम नहीं चला तो अब देश का ही नाम बदला जा रहा है। वास्तव में यदि भाजपा को लगता है कि केवल भारत ही नाम होना चाहिए तो फिर इस कदम को उठाने में उन्हें साढ़े नौ वर्ष क्यों लग गए? स्पष्ट है इसके पीछे कारण केवल विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना ही है । इतना सामान्य विवेक तो एक मतदाता में भी है कि भारत के प्रति अचानक सत्ताधारी दल में इतना प्रेम क्यों उमड़ा, इंडिया से इतनी नफरत क्यों होने लगी?

दूसरा सम्भावित विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। भाजपा को लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इससे अच्छा हथियार और कोई नहीं हो सकता । यह जानते हुए भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई प्रारूप भी सरकार ने अभी तक देश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, कैसे इस पर किसी भी दल या किसी भी समुदाय की आपत्ति ली जा सकती है? कुछ समय पूर्व यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पर सुझाव अवश्य कानून मंत्रालय ने मांगे थे । यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यदि कोई कानून संसद के द्वारा न भी बनाया जाए, तब भी इस पर चर्चा प्रारंभ करना और उसे बनाए रखना धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए एक अच्छा तरीका सत्ताधारी दल को लगता है ।

तीसरा विषय जो संसद के विशेष सत्र में लाया जाना संभावित लगता है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के संबंध में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही जिस प्रकार के निर्णय दिए गए हैं, उससे सरकार आशंकित है। हाल ही में मणिपुर की घटनाओं पर रिपोर्ट करने वाले एडिटर्स गिल्ड के चार पत्रकारों एवं उसके अध्यक्ष पर असम सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। सरकार किसी भी असहमति और विरोध को सहन नहीं कर पा रही है। वर्तमान में कई ऐसे प्रकरण नए-नए सामने आ रहे हैं जो सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं चाहे वह अडानी प्रकरण हो या कोई और। इसलिए सोशल मीडिया पर भी एक प्रकार से लगाम कसने हेतु कोई कानून लाया जा सकता है। ऐसा करके सरकार विरोध की आवाजों और उसकी अभिव्यक्ति को राष्ट्रद्रोह घोषित करते हुए, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास कर सकती है। देखना होगा कि क्या वास्तव में इस हेतु आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता में किसी संशोधन का कोई विधेयक सरकार द्वारा लाया जाएगा? उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में भाजपा एवं सत्ताधारी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है अत: किसी भी संशोधन को कानून बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता है ।

वास्तव में संसद में क्या बिल लाए जाएंगे या किस प्रकार की घोषणा संसद में सरकार एवं विशेष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी है यह सबके लिए उत्सुकता का विषय है। यह भी हो सकता है कि वे उपर लिखित सभी सम्भावनाओं को नकारते हुए कोई ऐसा निर्णय लें जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं हो। इसका उत्तर तो हमें संसद का विशेष सत्र प्रारंभ होने के साथ ही मिलेगा।

चौथा मुद्दा है, धार्मिक स्थलों के 1947 के स्वरूप को नहीं बदलने के संबंधित कानून में संशोधन करना। अयोध्या प्रकरण के बाद तत्कालीन सरकार ने एक कानून 1993 में बनाया था जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के समय धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था, उसके बारे में कोई विवाद नया नहीं खड़ा किया जाएगा एवं उसके स्वरूप को नहीं बदला जाएगा।

भाजपा एवं संबंधित संगठनों द्वारा विभिन्न मंदिर-मस्जिद के विवादों को उठाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं रहेगी और अनेक स्थानों पर मंदिर - मस्जिद के विवाद के माध्यम से समाज का ध्रुवीकरण कर आगामी चुनाव में बह संख्यक समाज के समर्थन के आधार पर जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकेगा। क्या ऐसा होगा, यह विशेष सत्र में देखना होगा।

पांचवां विषय भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नए नाम और रूप में संसद से पारित कराना है। विधेयक संसद में रखा जा चुका है। सम्भव है, विशेष सत्र में इसे कानून का रूप भी मिल जाए। इनके माध्यम से जहां न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने की बात की गई वहीं कुछ आरोपों में गिरफ़्तार लोगों को लंबे समय तक जेलों में बिना ज़मानत के लंबे समय तक जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

छठा विकल्प है, एक देश एक चुनाव की दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ाया जाय। इसका सबसे बड़ा लाभ सत्ताधारी दल को यह होगा कि राज्यों और संसद के चुनाव एक साथ होने पर इंडिया गठबंधन के दलों के आपसी मतभेद को भुनाना आसान होगा क्योंकि राज्यों में सबके अपने-अपने विरोधाभासी हित हैं। वर्तमान समय में अलग-अलग चुनाव होने पर जहां विधानसभा में वह एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस, बिहार में जनता दल यू और, कांग्रेस और राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता दल, दिल्ली में काँग्रेस और आम आदमी पार्टी, पंजाब में काँग्रेस और आप आदि। एक साथ चुनाव होने पर सब अपने-अपने स्थानीय क्षेत्र में ही व्यस्त हो जाएंगे और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी की राह बहुत आसान हो जाएगी। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार एक देश, एक चुनाव की अवधारणा को लागू करना कठिन है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जैसा कि उन्होंने अचानक राष्ट्रीय टी वी पर आकर नोटबंदी और पूरे देश में पूर्ण लोकडाउन की घोषणाएं की थीं। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को देश को झटका देने की आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्णय की क्रियान्वित में आने वाली कठिनाइयों तथा व्यवहारिकता की अधिक परवाह नहीं करते हैं। वह किसी भी निर्णय को पूरे इवेंट के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करने में माहिर हैं।

9 और 10 सितंबर को आयोजित G 20 सम्मेलन भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। देशवासियों को पता है कि G 20 प्रति वर्ष अलग अलग देश में आयोजित होता है। भारत 18 वाँ देश है जहां ऐसा हो रहा है। भारत के अलावा अन्य देशों ने इसे राष्ट्रीय इवेंट नहीं बनाया और न वहां की सरकारों ने इसका राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया। ऐसा करने के लिए चाहे देश के हजारों करोड रुपए खर्च हो जाएँ और दिल्ली के गरीब नागरिकों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर विस्थापित कर दिया जाय। विदेश के राष्ट्राध्यक्षों को हमारी गरीबी नहीं दिखाई दे, इसके लिए सफेद और हरे रंग के कपड़े से उनकी बस्तियों को छिपाने का प्रयास किया गया। ऐसा करते समय सरकार यह भूल जाती है कि आज के संचार क्रांति के युग में किसी से कुछ भी छुपाना सम्भव ही नहीं है।

सातवीं संभावना यह है कि महिला आरक्षण बिल को नए रूप में संसद में प्रस्तुत कर इसे पास कराया जाए। महिला आरक्षण का मामला वैसे तो कई वर्षों से लंबित है किंतु इसे लाकर महिला मतदाताओं का समर्थन करना सुनिश्चित किया जा सकता है।

आठवीं संभावना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में धारा 370 को हटाने से संबंधित हुई सुनवाई को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाए एवं वहां पर शीघ्र चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाया जाए। सरकार हालांकि अब तक कहती रही है कि वहां पर पुनर्सीमांकन का कार्य होने के पश्चात ही चुनाव कराए जा सकेंगे। सीमांकन का उद्देश्य यही है कि जम्मू क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर राज्य में भाजपा की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाए।

नवीं संभावना है यह भी व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा की सीटों के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए एवं तब तक के लिए लोकसभा के चुनाव स्थगित कर दिये जाएँ। नई संसद में लोकसभा में 745 सीटों की क्षमता रखी गई है। इसके परिणामस्वरुप सत्ताधारी दल को एक लाभ यह संभावित है कि दक्षिण की तुलना में उत्तरी भारत से अधिक सांसद चुनकर आ पायेंगे जहां उसे अधिक समर्थन प्राप्त है।

उपरोक्त लिखित सभी विकल्प तो केवल जनमानस के मन में संभावना के तौर पर हैं। वास्तव में संसद में क्या बिल लाए जाएंगे या किस प्रकार की घोषणा संसद में सरकार एवं विशेष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी है यह सबके लिए उत्सुकता का विषय है। यह भी हो सकता है कि वे उपर लिखित सभी सम्भावनाओं को नकारते हुए कोई ऐसा निर्णय लें जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं हो। इसका उत्तर तो हमें संसद का विशेष सत्र प्रारंभ होने के साथ ही मिलेगा। तब तक तो हमें 'बूझो तो जानें' जैसा खेल ही खेलते रहना पड़ेगा। एक सामान्य मतदाता तो यही अपेक्षा कर सकता है कि कोई इस प्रकार का निर्णय संसद में लिया जाए जिसका सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर पड़े और वह अधिक खुशहाल हो सके।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

चांदपुर खान में खुलेआम हो रहा है अवैध खनन

- पुरानी छावनी गांव के पास स्थित चांदपुर खान कई सालों से कागजों में बंद
- हकीकत में रोज यहां से अवैध तरीके से सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉली पत्थर भरकर ले जाते हैं
- 'ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, यह फॉरेस्ट वालों के क्षेत्र में आता है, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, फॉरेस्ट वालों से बात करें'

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर शहर के नजदीक पुरानी छावनी गांव के पास स्थित चांदपुर की खान पिछले कई सालों से कागजों में बंद है। लेकिन हकीकत बात ये है कि यहां अधिकारियों की नाक के नीचे बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। यहां से हर रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्राली अवैध तरीके से पत्थर भरकर ले जाते हैं। अधिकारी भले ही अवैध खनन पूरी तरह बंद होने के दावे करते हो। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है।

अकेली चांदपुर खान में ही रोज जेसीबी मशीन से खुलेआम बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। यहां से कई दर्जन ट्रैक्टर ट्राली एक साथ अवैध तरीके से पत्थर भरकर ले जाते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। धौलपुर जिले की जनता के सबसे लोकप्रिय और नंबर वन चैनल फर्स्ट ट्रेक ने अपने सूत्रों से चांदपुर खान की पड़ताल कराई तो चौकाने वाले हालात सामने आए। मौके पर कई ट्रैक्टर ट्रॉली यहां से अवैध तरीके से पत्थर भरकर ले जाते हुए मिले।

वहीं जेसीबी मशीन से बड़े स्तर पर यहां अवैध खनन होता हुआ मिला। अवैध तरीके से पत्थर भरकर ले जाते इन ट्रैक्टर ट्राली से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के पास झोपड़ी डालकर बैठे नाके के कर्मचारी रसीद काटकर इनसे पैसे की भी वसूली करते हैं। इसके अलाबा अवैध पत्थर से ओवरलोड भरे ट्रैक्टर ट्राली को धौलपुर शहर में आगे के पहिए उठे हुए हालत में सड़कों से निकलते हुए आसानी से देखा जा सकता है। जिससे हादसा होने की भी आशंकाएं बनी रहती है। बड़ी बात ये भी है कि जिस समय ये ट्रैक्टर ट्राली शहर से गुजरते हैं वह समय सुबह के समय स्कूली बच्चों का स्कूल जाने का होता है। जिससे बाजार में स्कूल जाने वाले बच्चे और स्कूली वाहनों की भीड़ रहती है।

इस मामले में खनिज विभाग धौलपुर के एमई मुकेश चंद्र मंगल का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, यह फॉरेस्ट वालों के क्षेत्र में आता है, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, फॉरेस्ट वालों से बात करें। वही इस मामले में वन विभाग धौलपुर के डीएफओ किशोर कुमार गुप्ता का कहना है कि एकाद दिन में दौरा करके पूरे हालात की जानकारी लेता हूं। हम अवैध खनन नहीं होने देंगे। जो भी अवैध खनन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बीकानेर मंडल के सभी कारागारों में क्षमता से अधिक बंदी

विरोधी गुटों के बंदी जेलों में आने से बढ़ी सुरक्षा की चिंता

- बीकानेर मंडल के 15 केन्द्रीय कारागारों में क्षमता से करीब दो गुना बंदी

बीकानेर, (कासं)। पुलिस के विशेष धरपकड़ अभियान से प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हो गए हैं। अकेले बीकानेर मंडल के 15 केन्द्रीय कारागारों की बात करें, तो इनमें क्षमता से करीब दो गुना बंदी अभी रखे हुए हैं। हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटरों की संख्या बढ़ने से जेल प्रशासन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

जेलों में दो विरोधी गिरोह के बदमाशों को रखने से जेल प्रशासन को फूंक-फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। प्रदेश की जेलों में हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर पहले भी कई बार वारदातों को अंजाद दे चुके हैं। जेल से बंदी रंगदारी, अपहरण और फिरौती वसूलने जैसी वारदातों में ज्यादा लिप्त दिखाई देते रहे हैं।

प्रदेश के 33 जिलों में जिला एवं सब जेलों के हालात विकट हैं। दस केन्द्रीय कारागार में 10 हजार 387 बंदियों को रखने की क्षमता है। कई जिला कारागार व उप कारागारों में क्षमता से दो गुना तक बंदी रखने पड़ रहे हैं। प्रदेश में 10 केन्द्रीय कारागार, 26 जिला जेल, 60 उप कारागार, सात महिला जेल, एक हाई सिक्युरिटी और एक किशोर सुधार बंदी गृह जैतारण में हैं।

जेल विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश की जेलों में औसतन साढ़े दस हजार बंदी हैं। इनमें 22 फीसदी सजायाफ्ता और 78 प्रतिशत विचाराधीन बंदी हैं। इसके अलावा पुलिस की ओर से पिछले आठ महीनों से विशेष धरपकड़ अभियान और चलाया जा रहा है। इसके चलते भी कई और बंदी बढ़ गए हैं। जेल में क्षमता से अधिक बंदी है। यह सही है लेकिन सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। सजायाफ्ता व विचाराधीन बंदियों की संख्या अधिक है। वर्तमान में पिछले दिनों चले पुलिस के विशेष अभियानों से भी बंदियों की संख्या बढ़ी है।

मेडिकल कॉलेज में कार्यशाला शुरू

जोधपुर (कासं)। एम. आर. यू., डॉ. एस एन मेडिकल कॉलेज और आईसीएमआर-एनआईआईएच, मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में पांच दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ।

डॉ. दिलीप कच्छावा, प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज ने डॉ. हिना तबस्सुम परियोजना समन्वयक-आईसीएमआर और डॉ. वंदना प्रधान प्रोजेक्ट पीआई मुंबई को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए कहा कि हमें रिसर्च को पश्चमी देशों के रिसर्च से तुलना ना करके हमें हमारे देश के हिसाब से रिसर्च करनी चाहिए और आज की तारीख में भारत में पूरे विश्व के सबसे यूवा रिसर्चस है तथा हमारी रिसर्च को पूरा विश्व मान्यता देने लगा है। उन्होंने कश्मीर से कन्या कुमारी तक के सभी चुनींदा सांइटीस्टों का जोधपुर की धरती पर स्वागत किया।

वीरांगनाएं व गैलेंट्री अवॉर्ड धारक सम्मानित

भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं ने अपनी समस्यायें बताईं

- सैनिक संवाद एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ

जोधपुर, (कासं)। जिला सैनिक कल्याण विभाग, जोधपुर के तत्वावधान में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में सैनिक संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए राज्यस्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष रामसहाय बाजिया ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बाजिया ने राज्य सरकार द्वारा सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि सैनिकों से संबंधित समस्याओं पर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान के सैनिक के फिजिकल कैजुअल्टी में परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से 45 प्रतिशत वेतन बढ़ाने जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड का भवन बनाने के लिए 20 करोड़ और कालवाड़ रोड पर 4000 वर्ग गज जमीन आवंटित की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की वीर नारियों की पेंशन चार हजार से बढ़ाकर दस हजार महिना तथा इसमें शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी, सैनिकों के डाटा का डिजिटलीकरण, शहीदों को मिलने वाले पैकेज को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने जैसे कई कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की बहुत सारी विसंगतियां थीं, जिन्हें दूर किया गया है। पूर्व में किसी भी एग्जाम में 2 साल तक का टाइम रहता था, उसे 5 साल किया गया है। सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था, उसे 35 प्रतिशत कर दिया गया। इसे और भी कम करते हुए पर्याप्त संख्या में पूर्व सैनिक नहीं मिलने पर 30 प्रतिशत तक लाया गया है।

सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष रामसहाय बाजिया ने सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में शहीद वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर एवं गैलेंट्री अवॉर्ड धरकों का साफा एवं पुष्पहार से सम्मान भी किया।

इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं ने अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया। कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (सेवा निवृत्त) दिलीप सिंह खंगारोत ने जिले के सैनिक कल्याण कार्यालय का विभागीय विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौरव सेनानी उपस्थित रहे।

"उत्कर्ष क्लासेज" का आरएएस अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट 17 को

सभी जिला मुख्यालयों पर आरएएस प्री- 2023 ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा

- टेस्ट के आधार पर हर विद्यार्थी की राज्य स्तर पर रैंकिंग भी तैयार की जाएगी
- मॉक टेस्ट में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्कर्ष एप में 2 ऑनलाइन टेस्ट भी निशुल्क दिए जाएंगे

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी आरएएस भर्ती परीक्षा प्री-2023 के प्रारम्भिक चरण का आयोजन अगले माह किए जाने की संभावना है। ऐसे में उत्कर्ष क्लासेस संबंधित परीक्षार्थियों के लिए सम्पूर्ण राज्य के गत 33 जिला मुख्यालयों पर आरएएस प्री-2023 का ऑफलाइन मॉक टेस्ट आगामी 17 सितंबर को प्रात: 10 बजे आयोजित करने जा रहा है। ओएमआर शीट पर होने वाले इस टेस्ट के आधार पर हर विद्यार्थी की राज्य स्तर पर रैंकिंग भी तैयार की जाएगी।

उत्कर्ष ग्रुप के चेयरमैन डॉ. निर्मल गहलोत ने बताया कि आरएएस अभ्यर्थियों के लिए इस रविवार संस्था द्वारा ऑल राजस्थान ऑफलाइन मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है जो कि विद्यार्थियों के लिए स्वयं की तैयारी को परखने का एक बेहतर अवसर है। यह मॉक टेस्ट जयपुर, जोधपुर सहित राज्य के पूर्व सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उनके मूल आवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा सकें। मॉक टेस्ट में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्कर्ष एप में 2 ऑनलाइन टेस्ट भी निशुल्क दिए जाएँगे। टेस्ट में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।

विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट की अहमियत पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि विदित है कि आरएएस भर्ती परीक्षा-2023 के तहत 905 पदों के लिए छह लाख नब्बे हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं जो प्रारम्भिक चरण की प्रतिस्पर्धा की संभावित कठिनता को दर्शाता है। ऐसे में विश्वसनीय स्तर पर तैयार मॉक टेस्ट में भाग लेकर अभ्यर्थी न केवल अपनी तैयारी की खूबियों व खामियों को जाँच सकते हैं बल्कि वास्तविक परीक्षा से पहले जरूरी हौसला भी जुटा सकते हैं।

परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा की तर्ज पर उत्कर्ष द्वारा आयोजित इस मॉक टेस्ट की रूपरेखा सिविल परीक्षाओं के अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, वहीं पेपर में शामिल प्रश्नों का चयन परीक्षा पैटर्न तथा नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया।

राशिफल मंगलवार 12 सितम्बर, 2023

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 11:01 तक, शिव योग रात्रि 1:11 तक, गर करण दिन 1:07 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:01 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 11:01 तक है। भद्रा रात्रि 2:22 से बुधवार दिन 3:35 तक रहेगी। आज भौम प्रदोष व्रत है। आज से जैन पर्युषण आरम्भ होंगे। (चतुरथी व्रत)

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:14 से 10:51 तक, लाभ-अमृत 10:51 से 1:35 तक, शुभ 3:28 से 5:00 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:14, सूर्यास्त 6:32

मेष

घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। अतिथियों के आगमन से भागदौड़ रहेगी। बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह

अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

धनु

अपनी कार्य योजना को आज और सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

वृष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

कन्या

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मकर

परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों मे उचित सफलता मिलेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-परिवार के कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

कुंभ

अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे।

कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। आर्थिक समस्या अभी यथावत बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।